



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]

No. 214]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 1, 1999/आश्विन 9, 1921
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 1999/ASVINA 9, 1921

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 33 (आर. ई. 99)/1997—2002

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1999

फा. सं. 01/94/180/197/एएमओओ/पालिसी-4.—सां आ. सं. 283(अ) दिनांक 31-3-1997 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में यथा अधिसूचित निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 4.11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) (आर. ई. 99), 1997—2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

1. पैराग्राफ 6.8 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

आवेदक स्व घोषणा के आधार पर सक्षम प्राधिकारी को ई.पी.सी.जी. लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते निम्न तालिका में दी गई वित्तीय शक्तियों के अनुसार मुख्यालय की ई.पी.सी.जी. समिति द्वारा संबंधों का अन्तिम निर्धारण किया जा सके। आवेदक को यह वचन देना होगा की यदि मुख्यालय की ई.पी.सी.जी. समिति जिम्स, फिक्सचर्स, डाईस, माउल्ट्स और स्पेयर्स सहित पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति नहीं देती है तो लाइसेंस धारक को ऐसी वस्तुओं पर 24% ब्याज सहित सीमा शुल्क देना होगा। लाइसेंस जारी करने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी लाइसेंस जारी करने के लिए 7 दिन के भीतर मुख्यालय की ई.पी.सी.जी. समिति की मंजूरी के लिए लाइसेंस की एक प्रति सहित आवेदन की प्रति भेजेगा।

लागत बीमा-भाड़ा मूल्य

2 करोड़ रुपए तक

2 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक

10 करोड़ से अधिक किन्तु 20 करोड़ तक

20 करोड़ से अधिक

सक्षम प्राधिकारी

संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी

संबंधित जोनल लाइसेंसिंग प्राधिकारी, जैसा कि परिशिष्ट 28 में दिया गया है

डी.जी.एफ.टी., नई दिल्ली

वाणिज्य सचिव

वैकल्पिक रूप से, आवेदक समिति से मंजूरी मिलने के पश्चात् लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मुख्यालय की ई.पी.सी.जी. समिति को आवेदन कर सकता है। तथापि, जहाँ लाइसेंस का मूल्य 20 करोड़ रु. से अधिक है, ऐसे मामलों में चाहे डी.जी.एफ.टी. को आवेदन किया गया हो, फिर भी इन आवेदनों को सचिवों की समिति के समक्ष रखना होगा।

2. सार्वजनिक सूचना संख्या 29 दिनांक 1-9-99 द्वारा शामिल किए गए पैराग्राफ 6.8 (ख) को हटा दिया गया है।

3. पैराग्राफ 7.6 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

(i) नयागतों के मामले में जिन्होंने निर्यात-आयात नीति के तहत किसी लाइसेंस का उपयोग नहीं किया है उन्हें नीति के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा 25 लाख रु. तक पहले शुल्क मुक्त लाइसेंस दिया जा सकता है।

इसके पश्चात आवेदक की प्रमाणिकता और पूर्णवृत्त की जाँच करने के पश्चात ही शुल्क मुक्त लाइसेंस दिया जा सकता है ताकि फार्म की प्रमाणिकता और मौजूदगी को सुनिश्चित किया जा सके। इस परियोजना के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है: आयकर विवरणी/बिक्रीकर विवरणी/केन्द्रीय उत्पाद प्रमाण पत्र/संबंधित प्राधिकारी/प्रशासनिक मंत्रालय से पंजीकरण प्रमाणपत्र/निदेशक/साझेदार/मालिक/ट्रस्टी के पासपोर्ट की फोटोप्रति अथवा लाइसेंसिंग प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए अन्य कोई सबूत हेतु दस्तावेज।

जहाँ कहीं प्रारम्भ में 25 लाख रु. से अधिक लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के लिए आवेदन किया गया है और लाइसेंस को 25 लाख रु. तक सीमित रखा गया है तो ऐसे लाइसेंस की जाँच करने के पश्चात् मूल रूप से किए गए आवेदन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अनुसार मूल्य में वृद्धि की जा सकती है।

जिन निर्यातकों ने निर्यात-आयात नीति के तहत किसी लाइसेंस का उपयोग नहीं किया है, किन्तु पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में निर्यात किया है, उन्हें लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के लिए अग्रिम लाइसेंस जारी किया जा सकता है, जिसका मूल्य पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में औसत पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) ऐसे निर्यातकों को अग्रिम लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं बशर्ते वे सीमा-शुल्क प्राधिकारी को 100% बैंक गारण्टी प्रस्तुत करें ताकि सीमा-शुल्क की छूट को शामिल किया जा सके। इस आशय का एक स्पष्ट पृष्ठांकन लाइसेंस/डी.ई.ई.सी. में किया जाएगा।

(iii) ऐसे निर्यातकों को पिछले लाइसेंस पर 50% निर्यात दायित्व पूरा करने के पश्चात ही दूसरा या परवर्ती लाइसेंस जारी किया जाएगा।

पैराग्राफ 7.5 के द्वितीय पैराग्राफ के प्रथम वाक्य को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

“ऐसे एक या अधिक लाइसेंसों का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य पिछले वर्षों के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से 100% से अधिक नहीं होना चाहिए न्यूनतम राशि 50 लाख रु.”

5. पैराग्राफ 7.5 के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाए :

“जिन मामलों में निर्यात दायित्व पूरा कर लिया गया है किन्तु एस.ए.एल.सी. द्वारा मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए, जैसा कि दूसरे पैराग्राफ में दिया गया है, लाइसेंस की हकदारी को निर्यात दायित्व पूरा करने और पिछले लाइसेंसों के संबंध में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति संबंधी सबूती दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, पुनः निर्धारित किया जा सके। तथापि ऐसे मामले में मानदण्डों का निर्धारण निलंबित होने पर बांड को समाप्त करने/निष्क्रिय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

6. वाक्य और अभिव्यक्ति “डैबोलिन हवाई अड्डा गोवा” को पैराग्राफ 8.40 के प्रथम वाक्य में शब्द और अभिव्यक्ति “हैदराबाद” के पूर्व शामिल किया जाए।

7. निम्नलिखित को पैराग्राफ 9.39 के रूप में जोड़ा जाए:

“ई.पी.सी.जी. योजना के तहत पुरानी आयातित पूंजीगत वस्तुओं को डि बान्ड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर भी आयात की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए 1-4-99 की अथवा इसके पश्चात आयातित पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्क के भुगतान पर किसी डी बॉन्डिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

8. परिशिष्ट 28 में उल्लिखित शब्द और अभिव्यक्ति “जोनल ई.पी.सी.जी. समिति/क्षेत्रीय ई.पी.सी.जी. समिति” को संशोधित करके “जोनल लाइसेंसिंग प्राधिकारी/क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी” पढ़ा जाए।

9. “आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज” शीर्षक के अधीन परिशिष्ट 11 (ख) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं।

(क) शुल्क छूट योजना के अधीन शुल्क मुक्त लाइसेंसिंग की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र की क्रम संख्या 1 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाए :

“नीति के पैराग्राफ 7.3, 7.4, 7.5 और 7.6 तथा इस प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) के पैराग्राफ 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 और 7.11 को देखें।”

(ख) “घोषणा/वचनबद्धता” की क्रम संख्या 6 के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा

(यह प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) के पैराग्राफ 7.5 के तहत किए जाने वाले आवेदनों के लिए ही लागू होगा।)

(ग) “आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज” शीर्षक के अधीन निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :

1. परिशिष्ट 34 के अनुसार आवेदन शुल्क के भुगतान के प्रमाणस्वरूप बैंक रसीद (2 प्रतियाँ)/डिमाण्ड ड्राफ्ट।

2. वैध आर.सी.एम.सी. की स्व प्रमाणित प्रति।

3. विशेष अग्रदाय लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र के मामले में परियोजना प्राधिकारी प्रमाणपत्र तथा अग्रिम अन्तर्वर्ती लाइसेंस के लिए आवेदन के मामले में अवैधता पत्र की एक प्रति।

10. पैराग्राफ 10.11 के अंतिम वाक्य में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा :

तथापि, राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 28-2-99 की अधिसूचना संख्या 20/99 की सूची 33 में विनिर्दिष्ट किसी बृहत विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए अपेक्षित सामान की आपूर्ति हेतु निर्यात आयात नीति के पैराग्राफ (क) (ख) (ग) और (घ) में यथा उल्लिखित मान्य निर्यात लाभ उपलब्ध होंगे बशर्ते कि ऐसे बृहत विद्युत परियोजना को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के किसी अधिकारी जिसका स्तर संयुक्त सचिव से कम का न हो, द्वारा (क) 1000 मेगावाट या अधिक क्षमता किसी अन्तः राजीय धर्मल प्लांट: अथवा (ख) 500 मेगावाट या अधिक क्षमता के अन्तर्राष्ट्रीय हाईड्रल पावर प्लांट के रूप प्रमाणित किया गया हो।

11. पैराग्राफ 10.12 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा :

(क) प्रथम उप पैराग्राफ के अंतिम वाक्य को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :

इसी प्रकार, उप ठेकेदार को, प्रक्रिया पुस्तक (भाग 1) के परिशिष्ट में यथा उल्लिखित मूल्य के लिए माल की उस सीमा तक मान्य निर्यात के लाभ उपलब्ध होंगे जिसकी उसने स्वयं या किसी बाहरी अन्य विनिर्माता से लेकर आपूर्ति की है और विनिर्माण किया है।

(ख) द्वितीय उप पैराग्राफ में उल्लिखित "सम्पूर्ण" शब्द को हटा दिया गया है।

12. परिशिष्ट-14 क के पैराग्राफ 2 के "*" के सामने अंतिम वाक्य को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :

पैराग्राफ 1 (क), (ख), (घ), (ङ) और (च) पर संविदा के लिए केवल संगत।

13. परिशिष्ट 27 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा :

(क) क्रम संख्या 20 के सामने कालम 4 में संशोधन करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा

पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा और संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार।

(ख) क्रम संख्या 24 के सामने कालम 4 को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा

मेघालय और मिजोरम।

14. परिशिष्ट 16च में निम्नलिखित को पैराग्राफ 8 के रूप में जोड़ा जाएगा।

हाई ग्रेड आइरन ओर

गोआ मूल और रेडी मूल के आयरन ओर को छोड़कर हाई ग्रेड अर्थात् 64% एफ ई आयरन ओर तथा इससे अधिक, के निर्यात के लिए प्रस्ताव इस समय एम एम टी सी द्वारा सरणीबद्ध किए जा रहे हैं और इसका निर्यात अनुमोदन बोर्ड द्वारा वार्षिक मात्रा आबंटन के अधीन होगा।

15. निम्नलिखित को परिशिष्ट 32क के अन्तर्गत एक एजेंसी के रूप में जोड़ा जाएगा :

22. एस जी एस इण्डिया लिमिटेड,

ऊया हाउस,

210, ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट,

फेज-3,

नई दिल्ली-110020

दूरभाष: 011-6824178/182/781/941/952/954/6929672/73/74/75

16. पैराग्राफ 15.15 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"इसी प्रकार, जिन मामलों में निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति से पूर्व सीमाशुल्क प्राधिकारियों को माल सौंप दिया जाता है लेकिन वास्तविक निर्यात, निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति के बाद होता है, ऐसा निर्यात, निर्यात दायित्व अवधि के भीतर माना जाएगा और निर्यात दायित्व की पूर्ति हेतु मान्य होगा।"

17. पैराग्राफ 15.4 के उप पैराग्राफ (ख) के अंतिम वाक्य को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

"परन्तु, तथापि, आयात-निर्यात कोड जारी करने वाला लाइसेंसिंग प्राधिकारी 5000 रुपए के जुर्माने की अदायगी के परिणामस्वरूप विलम्ब को माफ कर सकता है।"

18. परिशिष्ट-51ख में उल्लिखित "गैर-तरजीही हेतु उद्गम का प्रमाणपत्र" जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों की सूची में शीर्षक "महाराष्ट्र" के नीचे निम्नलिखित को एजेंसी के तौर पर जोड़ा जाएगा।

मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन,

यजाज भवन, पी-2, एम आई डी सी,

स्टेशन रोड, औरंगाबाद-431005

टेलीफोन : (0240)-324509/355090

फैक्स: (0240)-333029

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

MINISTRY OF COMMERCE**PUBLIC NOTICE NO. 33 (RE-99)/1997—2002**

New Delhi, the 1st October, 1999

F. No. 01/94/180/197/AMOO/PL-IV.—In exercise of the powers conferred under paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997—2002, as notified in the Gazette of India Extraordinary, Part-II—Section 3—Sub-section (ii) vide S.O. No. 283(E) dated 31-3-1997, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook of Procedures (Vol. 1) (RE-99), 1997—2000.

1. Paragraph 6.8 shall be amended to read as under:

The applicant may apply for EPCG licence to the competent authority on the basis of self declaration subject to final fixation of nexus by Hqrs. EPCG Committee as per the financial power given in table below. The applicant shall give an undertaking that in case the Hqrs. EPCG Committee disallows the capital goods including Jigs, Fixtures, Dies, Moulds and spares, the licence holder shall pay Customs duty together with 24% interest on such goods. The competent authority, after issuance of the licence, shall forward a copy of the application alongwith a copy of the licence to the Hqrs. EPCG Committee for its approval within 7 days of the issuance of the licence.

CIF value	Competent Authority
Upto Rs.2 crore	Regional Licensing Authority concerned
Above Rs.2 crore and upto Rs.10 crore	Zonal licensing authority concerned as given in Appendix- 28.
Above Rs.10 crore but upto Rs.20 crore	DGFT, New Delhi
Above Rs.20 crore	Commerce Secretary

Alternatively, the applicant can apply to Hqrs. EPCG Committee for obtaining a licence after approval by the Committee. However, in cases where the value of the licence is more than Rs.20 crore, such cases, though applied to DGFT, shall be placed before the Committee of Secretaries.

2. Paragraph 6.8(B) incorporated by Public Notice No.29 dated 1.9.99 stands deleted.

3. Paragraph 7.6 shall be amended to read as under:

In the case of newcomers, who have not availed any licence under the Exim Policy, first duty free licence upto Rs.25 lakhs may be granted by the licensing authority in accordance with the policy.

Thereafter, duty free licences may be granted only after verifying the bonfides and antecedents of the applicant to ensure the genuineness and existence of the firm. For this purpose, the applicant shall be asked to produce a copy of the any one of the document, namely, Income Tax Return/Sales Tax Return/ Central Excise Certificate/ Registration certificate from the concerned authority/Administrative Ministry/Photocopy of the passport of the Director/Partner/Proprietor/ Trustee or any other documentary evidence to the satisfaction of the licensing authority.

Wherever the initial application has been filed for a CIF value of more than Rs.25 lakhs and the licence has been restricted to Rs.25 lakhs, such licence after verification may be enhanced for a value originally applied for or as approved by the competent authority.

In such cases of exporters who have not availed any licence under the Exim Policy but have exported in the preceding three licensing years, advance licence may be issued for a CIF value not exceeding average fob value in preceding three licensing year.

ii) Such expoters shall be issued advance licence subject to furnishing 100% Bank Guarantee to Customs authority to cover exemption from customs duties. Specific endorsement to this effect shall be made in the licence/DEEC.

iii) Such exporters shall be issued second and subsequent licences only after fulfilling 50% of the export obligation on previous licences.

4. The first sentence of second paragraph of paragraph 7.5 shall be amended to read as under:

“The CIF value of one or more such licences shall not exceed 100% of the fob value of preceding years exports subject to a minimum of Rs.50 lakhs”.

5. The following shall be added at the end of paragraph 7.5:

“In such cases where the export obligation is completed pending fixation of norms by SALC, the entitlement for the licence as given in second paragraph may be recredited upon production of documentary evidence showing fulfilment of export obligation and realisation of foreign exchange in respect of the

previous licences. However, bond waiver/ redemption shall not be allowed pending fixation of norms in such cases".

6. The word and expression "Dabolin Airport, Goa" shall be included before the word and expression "Hyderabad" in the first sentence of paragraph 8.40.

7. The following shall be added as paragraph 9.39:

"Debonding of capital goods imported as second hand shall not be allowed under EPCG Scheme. Moreover, no debonding on payment of applicable duties shall be allowed in respect of second hand capital goods imported on or after 1.4.99 for a period of atleast 3 years from the date of imports".

8. The word and expression "Zonal EPCG Committee/Regional EPCG Committee" appearing in Appendix-28 shall be amended to read as "Zonal licensing authority/Regional licensing authority".

9. The following amendments shall be made in Appendix-11B, under the heading "The documents to be enclosed with the application form" ,

a) The S.No.1 of the Application form for grant of duty free licence under Duty Exemption Scheme shall be amended to read as under:

"Please see paragraph 7.3, 7.4, 7.5 and 7.6 of the Policy and paragraph 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 and 7.11 of this Handbook (Vol.1)".

b) The following shall be added at the end of S.No.6 of "Declaration/Undertaking"

(This is applicable only for the applications under paragraph 7.5 of the Handbook (Vol.1).

c) The following amendment shall be made under the heading "Documents to be enclosed with the application form".

1. Bank Receipt (in duplicate) /Demand Draft evidencing payment of application fee in terms of Appendix-34.
2. Self certified copy of valid RCMC.
3. Project Authority Certificate in cases of application for Special Imprest Licence and a copy of invalidation letter in case of application for Advance Intermediate Licence.

10. The following amendment shall be made in the last sentence of paragraph 10.11:

However, supply of goods required for setting up of any mega power projects specified in list 33 of Department of Revenue notification No.20/99 dated 28.2.99, as amended from time to time, shall be eligible for deemed exports benefits as mentioned in paragraph 10.3(a)(b)(c) & (d) of the Exim Policy, if such mega power project is - (a) an inter state thermal power plant of a capacity of 1000 MW or more; or (b) an inter-state hydel power plant of a capacity of 500 MW or more-as certified by an officer not below the rank of a Joint Secretary, Government of India in the Ministry of Power.

11. The following amendment shall be made in paragraph 10.12:

a) The last sentence of first sub paragraph shall be amended to read as under:

Similarly, the deemed exports benefits to the sub contractor would be available to the extent of goods that are manufactured and supplied by him or outsourced from other manufacturers, for the value as indicated in Appendix-14A of Handbook (Vol.1).

b) The word "entire" appearing in second sub-paragraph stands deleted.

12. The last sentence in paragraph 2 of Appendix-14A against " * " may be amended to read as under:

Relevant only for contract at paragraph 1 (a), (b), (d), (e) and (f).

13. The following amendment shall be made in Appendix-27:

a) column 4 against S.No.20 shall be amended to read as under

West Bengal, Sikkim, Tripura, and Union Territory of Andaman and Nikobar.

b) Column 4 against S.No.24 shall be amended to read as under:

Meghalaya and Mizoram.

14. The following shall be added as paragraph 8 in Appendix 16-F:

High Grade Iron Ore

Proposal for export of high grade i.e 64% Fe Iron ore and above except iron Ore of Goa origin and Redi origin are presently canalized through MMTC and its export would be subject to annual quantity allocation by the Board of Approval.

15. The following shall be added as an agency under Appendix-32A:

22. SGS India Limited,

Usha House

210, Okhla Industrial Estate,

Phase-III

New Delhi-110020

Tel: 011-6824178/182/781/941/952/954

6929672/73/74/75

16. The following shall be added at the end of paragraph 15.15:

“Similarly, in such cases where the goods are handed over to the customs authorities before the expiry of the export obligation period but actual exports takes place after expiry of the export obligation period, such exports shall be considered within the export obligation period and taken towards fulfilment of export obligation”.

17. The last sentence of sub paragraph (b) of paragraph 15.4 shall be amended to read as under:

“provided, however,, the licensing authority issuing the IE code may condone the delay on payment of a penalty of Rs.5000/-“

18. The following shall be added as an agency in Appendix 51-B under the heading “Maharashtra” in the list of agencies authorised to issue “Certificate of Origin for the non preferential”.

Marathwada Industries Association,

Bajaj Bhavan, P-2, MIDC, Station Road,

Aurangabad-431 005

Tel: (0240) - 324509/355090

Fax: (0240)- 333029

This issues in public interest.

N.L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade